

बिहार में 3.7 लाख अयोग्य मतदाता

चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जो 24 जून, 2025 को दर्ज 7.89 करोड़ की तुलना में लगभग 6% कम है। यह अंतर उस अवधि के पश्चात् सामने आया है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में तीन माह के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की थी।

मुख्य बटु

Bihar Voter List Revision 2025: Summary

Category	Number	Details
Names Deleted	65 lakh	Initial deletions at draft roll stage
Additional Deleted	3.66 lakh	Deleted after draft roll publication
Total Deletions	68.5 lakh	Combined (initial + additional)
Names Added	21.53 lakh	New electors before final roll
Net Change	-47 lakh	Total drop in voter count (deletions minus additions)

■ वलुपन और परवलरुधन:

- मसुदा सूची से 65 लाख नाम हटा दलल गल, जनलमें प्रमुख श्रेणललें मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेशन थीं। दावलें तथा आपतुतललें के नपलटारे के बाद अंतलमल चरण में 3.66 लाख अतरलकलत नाम हटा दलल गल।
- हटाए गए गैर-नागरलकलें या वदलशललें की संख्यल नगण्य थी।
- अंतलमल सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। 1 अगस्त, 2025 को जलरी मसुदा सूची (7.2 करोड़) की तुलना में मतदाताओं की संख्यल में 17.9 लाख की वृद्धलहुई।

■ ललल प्रतनलधलतलव:

- महलला मतदाताओं का प्रतशलत जनवरी में 47.75% था, जो SIR के पूरा होने के बाद थोड़ा घटकर 47.15% हो गया।

■ वैधानलकल पहलु:

- सरवुऑऑ न्यलयालय का नरलणय: न्यलयालय ने नरलणय दललल का आधलर को पहचान के 12वें दस्तलवेज के रूप में शामिल कलल जाएगा, जलसलसे बहुषलकरण की संभलवना बढ़ सकती है।
- अपील प्रकरललल: नाम हटाए जाने से असंतुषुट मतदाता जलला मजसलट्रेट और मुख्य नरलवाचन अधलकलरी के समकुष अपील कर सकते हैं।

मतदाता सूची का वशलष गहन पुनरीकुषण (SIR)

■ मतदाता सूची:

- मतदाता सूची (जसलें वुटर लसलट या इलेकुुटरल रजसलटर भी कहा जाता है) कसलल वशलष नरलवाचन कुषेत्र में सभी युुग्य और पंजीकुत मतदाताओं की आधलकलरलकल सूची है।
- इसका उपयुुग मतदाताओं की पहचान सतुयापतल करने तथा चुनावुु के दुरलरलन नषलपकुष एवं पारदरशी नरलवाचन प्रकरललल सुनशलचतल करने के ललल कलल जाता है।
- मतदाता सूचललें भारत नरलवाचन आयुुग (ECI) दवलरा जनप्रतनलधलतलव अधनलललम, 1950 के तहत तैयलर की जाती हैं। इसमें गैर-नागरलकल शामिल नहीं होते (धलरा 16) तथा 18 वरुष या उससे अधलकल आयुु के नागरलकल जो सामान्यतः नरलवाचन कुषेत्र में नवलस करते हैं, उनुुें शामिल

किया जाता है (धारा 19)।

■ **वर्षिक गहन पुनरीक्षण (SIR):**

- SIR एक केंद्रीकृत, समयबद्ध, घर-घर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही करने के लिये बृथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs) द्वारा संचालित की जाती है।
- यह नए पंजीकरण, वल्लोपन और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी तथा वसिगतियों से मुक्त हो।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 भारत नरिवाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने का अधिकार देती है, जिसमें दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय वर्षिक संशोधन करना भी शामिल है।
- **SIR का संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 324** भारत के नरिवाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 326** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जब तक कि उन्हें आपराधिक दोषसिद्धि, वकृत मस्तपिक् या भ्रष्टाचार के कारण कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।
 - **अनुच्छेद 327** वधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
 - **अनुच्छेद 328** राज्य की वधानमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- **न्यायिक स्थिति:**
 - मोहदिर सहि गलि बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और नपिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 324 के तहत ECI की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनरमतदान का आदेश देना भी शामिल है, और इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 329(b) के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है।
 - इसमें स्पष्ट किया गया कि यदि अनुच्छेद 327 और 328 के तहत कानून किसी भी पहलू पर मौन है तो भारत नरिवाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।
 - साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि यदि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण है, फरि भी असाधारण परिस्थितियों में ECI त्वरति और व्यावहारिक नरिणय ले सकता है।
- **पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण:** देश के वभिन्न भागों में वर्ष 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में वर्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) आयोजित किये गए थे। बिहार में अंतिम SIR वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था।